(घ) और (ङ) लोहे और इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में "इस्पात निर्यातक मंच" गठित किया है। प्रमुख इस्पात उत्पादक/एसोसिएशन इस मंच के सदस्य हैं।

सरकार ने निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(1) बाजार विनिमय दर पर निर्यात आय का पूर्ण परिवर्तनीयता।

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को कच्चे माल की अपनी आवश्यकता को बिना शुल्क के आयात करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

(3) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री के लिए दिया गया शुल्क वापिस करना।

(4) निर्यात से अर्जित आय को खंड 80 एच एच सी के अन्तर्गत आयकर से छूट देना; और

(5) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों पर ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) योजना के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट दरों में वृद्धि करना।

**Setting up of Vijayanagar Steel Plant**

2851. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the progress so far made with regard to the setting up of Vijayanagar steel plant in Karnataka; and

(b) the time by when the plant is likely to be set-up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) The Union Government had incorporated a new company viz. 'Vijayanagar Steel Limited' in December, 1982 to set up Vijayanagar steel plant. Land was acquired for the purpose. However, this did not materialise. Subsequently, Government of Karnataka entered into an Agreement with Jindal Iron & Steel Company Ltd. (JISCO) to set up an integrated steel plant. The State Government also signed an MOU with Mukund Ltd. for setting up of a steel plant. Both these plants were proposed on the same land.

As per available information, while no material progress has been made in the case of Mukund's steel plant, JISCO have formed a new company viz. Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (JVSL) which has made substantial progress. JVSL has already commissioned its hot strip mill during June, 1997. Further, its first phase of iron and steel making facility is likely to be commissioned by August, 1998. The second phase is likely to be commissioned by March, 1999. The investment made in the project upto the end of May, 1998 is around Rs. 3250 crores.

**हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी**

2852. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) कम्पनी द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही निर्माण परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ग) कम्पनी के वार्षिक लाभ और हानि की विगत पांच वर्षों की स्थिति क्या है; और

(घ) इस कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान न करने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस):** (क) आज तक की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

(एच०एस०सी०एल०) में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:—

| | | |
|---|---|---|
| कार्यपालक | : | 1565 |
| गैर-कार्यपालक/श्रमिक | : | 12452 |
| कुल | : | 14017 |

(ख) 1.6.1998 तक की स्थिति के अनुसार, एच०एस०सी०एल० के पास 61 परियोजनाएं हैं।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

| वर्ष | हानि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 1993-94 | 86.50 |
| 1994-95 | 95.85 |
| 1995-96 | 114.64 |
| 1996-97 | 132.57 |
| 1997-98 (अनन्तिम) | 225.90 |

(घ) एच०एस०सी०एल० में वेतन न दिए जाने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने फलस्वरूप मजदूरी तथा वेतन में वृद्धि।

(2) अतिरिक्त कार्यबल।

(3) कारोबार में कमी।

(4) ग्राहकों से देय राशि की वसूली में विलम्ब।

**Sail Losses**

2853. SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Steel Authority of India Limited (SAIL) has been incurring heavy losses during the recent period;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the units under Steel Authority of India Limited (SAIL) are suffering from heavy inventory stock for some time; and

(d) if so, the unit-wise details in this regard and also the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) Steel Authority of India Limited (SAIL) has been consistently making profits for the last more than 10 years. It has earned a Net Profit (before tax) of Rs. 149 crores (provisional) in the last year, i.e. 1997-98.

(c) and (d) Due to adverse market situation arising out of depreseed demand and surplus availability, inventory had registered an increase in the units of Steel Authority of India Limited., However, during the first three months of the current financial year, inventory has been brought down from approximately 1.23 million tonnes (provisional) on 1st April, 1998 to approximately 1.14 million tonnes on 1st July, 1998.

**Mining Projects in Private Sector**

2854. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of projects in the mining industry that had been given to the private sector;

(b) the number out of them given to the foreign mining companies;

(c) the modalities adopted for giving the mining rights;

(d) the overall benefits of such leasing of mining rights to private parties;

(e) whether Government have identified any new areas for mining of precious metals in the country; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Mining acitivity in the country has historically been undertaken both, by public sector as well as private sector comapnies. As on May, 1998 there were 8,752 mining leases which have been granted to private sector in the country.

(b) and (c) Prospecting and mining rights are granted by the concerned State